



## GENERAL STUDIES (Test-18)

निर्धारित समय: तीन घंटे  
Time allowed: Three Hours

**GSM (M-I)-2418**

अधिकतम अंक: 250  
Maximum Marks: 250

2126

Name: Khetdan Charan

Mobile Number: \_\_\_\_\_

Medium (English/Hindi): HINDI

Reg. Number: \_\_\_\_\_

Center & Date: \_\_\_\_\_

UPSC Roll No. (If allotted): \_\_\_\_\_

### प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

### QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)

Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)

Reviewer (Signature)



## Feedback

- |   |  |
|---|--|
| 1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)      | 2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)     |
| 3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)  | 4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)                 |
| 5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता) | 6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता) |
-



1. संसदीय उत्तरदायित्व के स्तर को निर्धारित करने में विपक्षी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये।

(150 शब्द) 10

The role of opposition parties is critical in determining the level of parliamentary accountability. Discuss.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)

विपक्षी दल ब्रिटिश सैंडो कैबिनेट  
की तरह कार्य करते हैं जिनको भारत में 1960 ई.  
के दशक में मान्यता प्रदान की। विपक्षी दल के  
लिए लोकसभा में 10% सीट अनिवार्य हैं।

# भूमिका

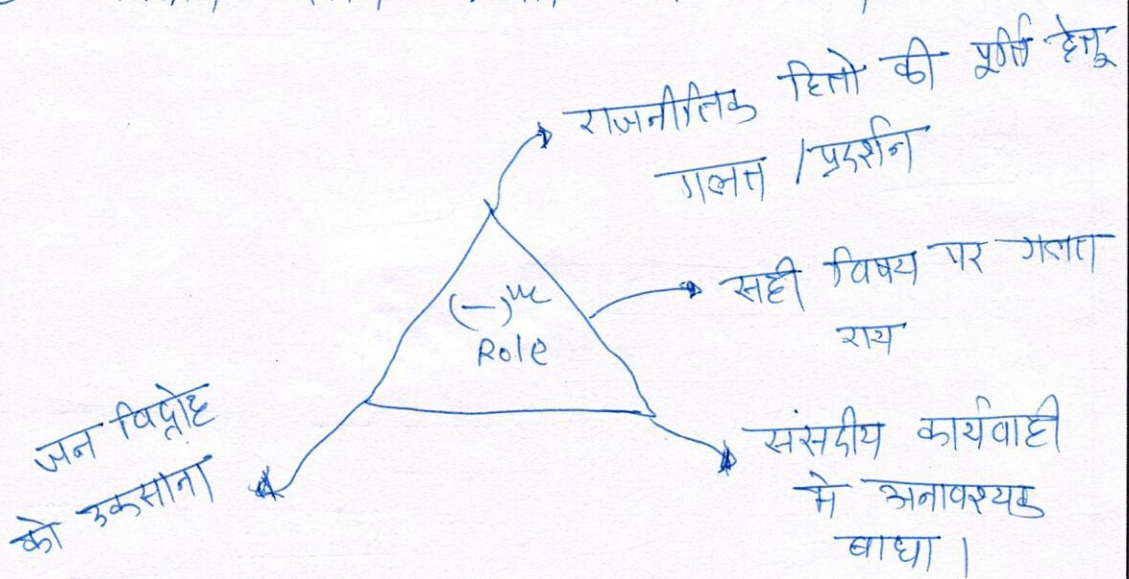
① संसदीय संतुलन निर्माण

- सरकार पर नियंत्रण
- जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती हैं।
  - प्रश्न काल में तारांकित,  
अतारांकित द्वारा।
  - कठौती प्रस्ताव द्वारा

② नीतियों की समालोचना करने व उनको  
जागू करने में योगदान, मतमूल्य व  
दिशा-निर्देश → नारी शक्ति चंदन में सहयोग



- ③ सरकारी मितव्ययता के पालन पर बल
- ④ राज्यीय जवाबदेहिता का कार्य ।  
(ex. लोकलेखा समिति अध्यक्ष विपक्ष नेता होता है)
- ⑤ अपने लोगो की माँगों को रखना ।
- ⑥ राजनीतिक बेराबंदी, निरकुशकारी प्रवृत्ति को रोकना
- ⑦ संविधान पालन करवाने पर बल ।



जरूरत • Youth parliament को बढ़ावा ।

- विपक्षी दलों का संवैधानिकीकरण करके संवैधानिक जवाबदेहिता लागू की जाए ।
- आलोचना के बजाय समालोचना पर बल देने की प्रवृत्ति बढाई जाए ।



2. महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10  
Discuss the role of Self-Help Groups in widening women's labour force participation. (150 words) 10

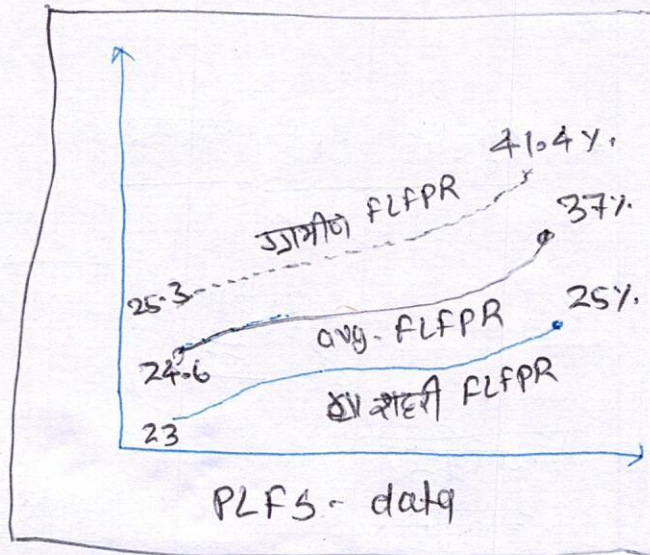
उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)

Ans

वर्ल्ड बैंक के अनुसार स्वयं सहायता समूह के गैर राजनीतिक संगठन होते हैं जो साक्षात्संसाधनों के द्वारा साक्षात्समृद्धि सुनिश्चित करते हैं।

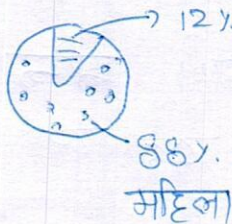
# SHGs महिला रोजगार

→ महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है।



Ex. → एराकुआनेमिन्स → कॉफी की खेती के लिए महिलाओं का सहयोग रोजगार

→ SHGs से प्राप्त कुल रोजगार में 88% महिलाएं हैं।



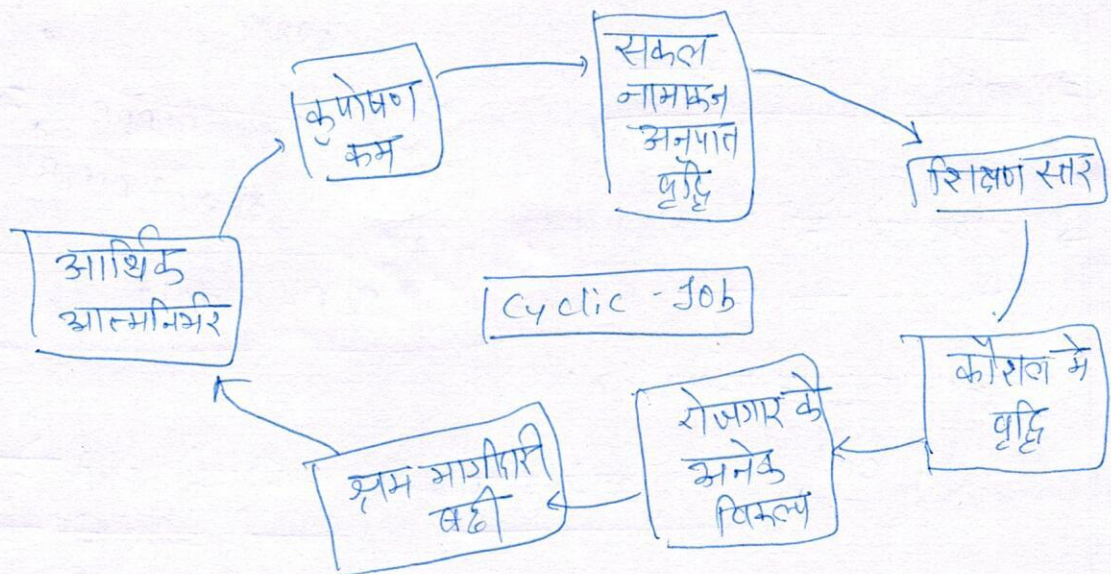
→ 12 करोड़ परिवारों को रोजगार देते हैं।



# SHGs - कृषि में अधिक कार्यरत हैं जिसके कारण महिलाओं से जुड़ पाते हैं तथा इनको रोजगार प्रदान करते हैं EX: केरल मसाला समूह → महिलाओं

के खाद्य प्रसस्करण से जोड़ते हैं  
रोजगार के लिए अवसर

# Cyclic Job अवसर



लेकिन SHGs के ग्राभीण जुड़ाव, तद्वत तक पहुँचें तथा SHGs में उत्पन्न गुटबाजिता को रोककर SHGs का लोकतांत्रिकरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त करने पर बल देना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)



3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलने से समाज के कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बल मिला है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The approach to welfare is wholesome and whole-of-society, with increasing private sector participation through Corporate Social Responsibility(CSR). Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)

Ans

CSR जाँची जी के न्यासधारिता

सिद्धान्त पर आधारित है जो कॉर्पोरेट निगम को सामाजिक के लिए जनकल्याण करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कम्पनी Act - 2013 के तहत कम्पनी जिसका नेटवर्क 100000, लाभ - 500 है उनके अपने 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% CSR पर खर्च करना चाहिए।

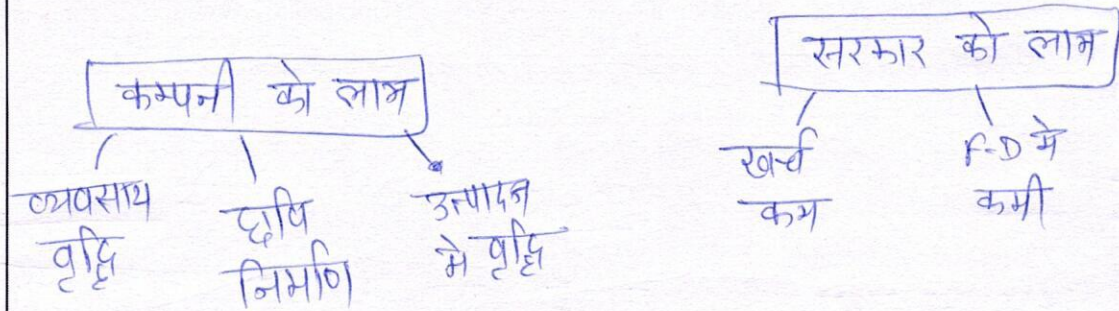
# CSR + Pvt के समाज को लाभ

- बेहतर सुविधाएँ → महेन्द्रा SEZ - नन्ही कली (महिला शिक्षा)
- WASH प्रोजेक्ट के CSR योजना खर्च से स्वास्थ्य मानकों में सुधार।

- CSR खर्च ने स्थानीय निकायों को अतिरिक्त वित्त (निधि) की प्राप्ति

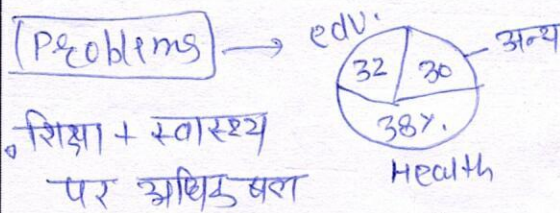


③ कम्पनी व समाज के मध्य दूरी में कमी

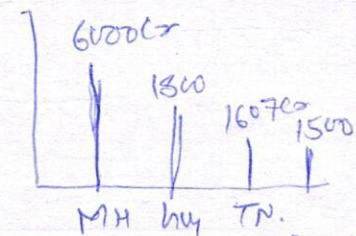


उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)

लेकिन CSR के प्रति सकारात्मक  
दृष्टिकोण की कमी रही जिसके कारण सामाजिक  
प्रभाव वांछित लक्ष्यों तक प्राप्त नहीं हो सका।



- ② ग्रामीण सम्पर्क नहीं  
③ N-E तक विस्तार नहीं



④ कम्पनियां से कोर्पोरेट टैक्स  
के रूप में लेती हैं।

⑤ CSR अंकेक्षण में कमी।

केवल 5 राज्यों में सीमित

# way forward :-

- ① इंजेक्ती स्त्रीनिवासन कमेटी की सिफारिशें मानी जाएं
- ② CSR implementing authority का गठन।
- ③ ग्रीनवांशिग पर रोक लगाई जाए।



4. व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के क्रम में मानसिक स्वास्थ्य कम ध्यान दिये जाने वाला लेकिन प्रभावशाली चालक है। चर्चा कीजिये। इस संबंध में सरकार की सकारात्मक नीति क्या है? 1 mp. (150 शब्द) 10

Mental health is a less seen yet principally impactful driver of individual and national development. Discuss. What is the Government's positive policy momentum in this regard? (150 words) 10

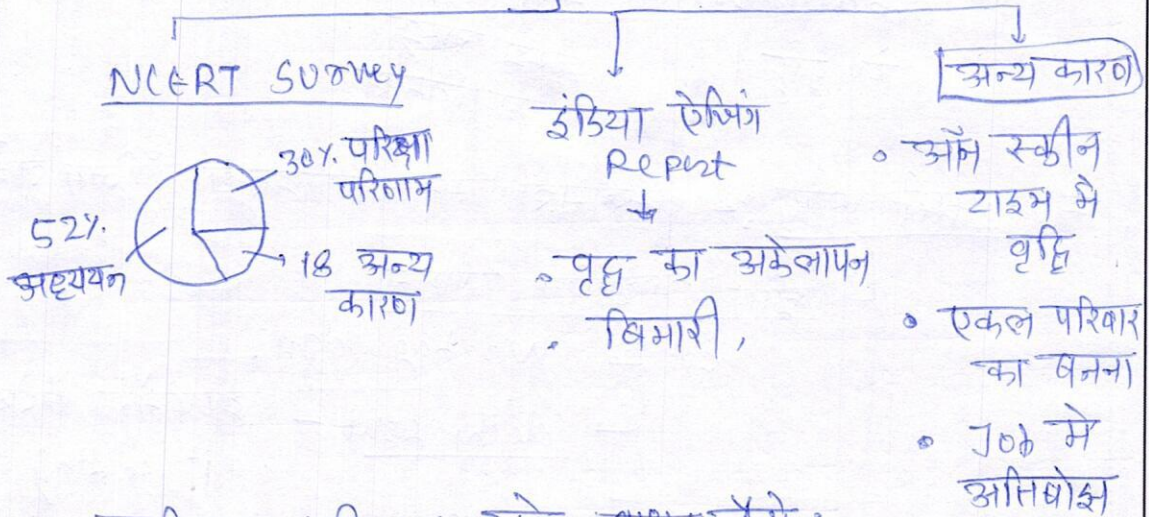
उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)

Ans

### Economic Survey 2023-24

के अनुसार विश्व में प्रत्येक 8 में से 1 तथा भारत में प्रत्येक 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है।

### मानसिक अस्वास्थ्य के कारण



# व्यक्तिगत विकास में बाधक कैसे :-

- ① कार्य दक्षता में कमी → काम से ऊषासन का विकास
- ② मानसिक तनाव में वृद्धि



3) व्यक्तिगत उत्पादकता में कमी।

4) पीड़ित रहने व मनोविकारों की उत्पत्ति

निरंतरता

आत्मदंष्ट्या

अविश्वास

सामाजिक  
कटाव

सामाजिक विखण्डन

# राष्ट्रीय विकास में बाधक → व्यक्तिगत उत्पादकता में कमी

Govt. Health  
Expenditure  
में वृद्धि।

अस्वस्थ मानव  
से  
अस्वस्थ राष्ट्र  
का विकास

समर्थन में कमी

NDP में कमी।

सरकारी प्रयास :- नेशनल मेन्टल हेल्थ पॉलिसी लाई गई।

स्रोत आधारित उदाहरण

Ex → No bag day.  
delhi govt - टैपिनैस सेलेक्स  
(1<sup>th</sup> to 8<sup>th</sup>)  
kota Coaching - No mark No  
Rank only test

गोवर्त Health इंश्र के लिए अभियान

women mental health के लिए

- सखी सेन्टर, SHE BOX, 00 helpline  
नंबर



5. ग्रामीण भारत के शासन में सुधार हेतु शुरू की गई विभिन्न डिजिटलीकरण पहलों पर चर्चा कीजिये।

(150 शब्द) 10

Discuss the multiple digitization initiatives that have been unfolding in rural India to improve governance.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)

Ans

"e-governance / डिजिटलीकरण वह प्रक्रिया है जो कंप्यूटर के कुछ कुंजियों से लाखों चेहरों पर मुस्कान ला सकता है।"

• PM. नरेन्द्र मोदी •

# ग्रामीण डिजिटलीकरण के लिए :-

① भूमि रिकॉर्ड प्रबन्धन के दाल-ही में स्वामित्व योजना प्रारम्भ की गई।

साधन/उद्देश्य

- किसान/भू-धारण पंजीकरण
- खसरा नम्बर आंशिक
- भू-माप, भू-उपयोग जानकारी
- भू-अधिग्रहण में सहायक

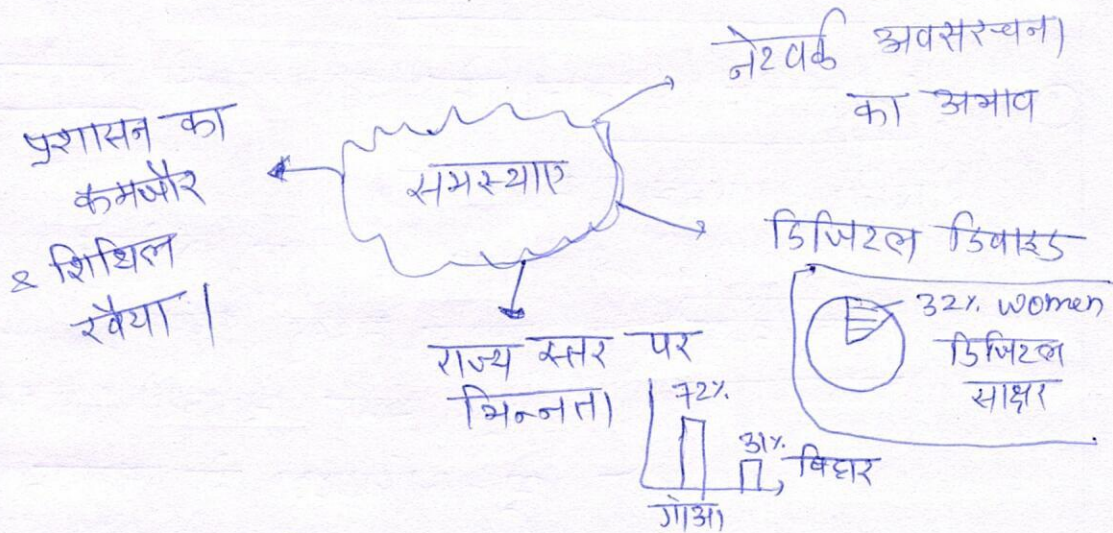
② ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क सुविधा के लिए Nehp योजना। → वाइरलेस कनेक्शन दिए गए।

③ ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के डिजिटलीकरण के लिए e-NAM व kshAM पोर्टल बनाए गए।



अर्थ (आर्थिक सर्वे. 2023-24 के अनुसार e-NAM  
पर 77 लाख किसान & 2.56 लाख व्यापारी रजि.  
हो गए)

- पंचायतो के डिजिटलकरण के लिए राजीव गांधी  
केन्द्रों की स्थापना।
- Bank-e-mitrag, साइबर केंद्रों की स्थापना।



# 3 way forward

- ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान।
- ग्रामीण भाषा / क्षेत्रीय भाषा में डिजिटलीकरण करें।
- 'ग्रामीण डिजिटल मित्रों' का विकास करें।



6. भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस लिखित संघीय संविधान को नम्यता (Flexibility) प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विस्तारपूर्वक समझाइये। (150 शब्द) 10

A distinctive feature of the Indian Constitution is that it seeks to impart flexibility to a written federal Constitution. Elaborate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)

Ans

केशवानंद भारती काद - 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय ढाँचे को संविधान का मूलभूत ढाँचा माना है।

संघवाद  
तत्त्व

→ शक्तियों का विभाजन Art-246 {  
केन्द्र सूची = 100  
राज्य = 47  
समवर्ती = 61

→ संघ व केन्द्र की पृथक-पृथक सरकारें,

→ न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालयों का गठन

अलग से वज्र पारित करने की शक्ति

— राज्य के स्वयं के tax, आर्थिक नीतियां इत्यादी।

→ लिखित, कठोर संविधान, संविधान संशोधन में राज्य को महत्व।

राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व



लेकिन यह संविधान कठोर न  
होकर नम्य है जिससे निम्न उदाहरण है-

- संसद का पंचस्य
  - राज्य सूची → अम-249, अम-250, अम-251  
पर कानून | राज्य सभा दो राज्यों आपात  
द्वारा 2/3 बहुमत के कदम के समय  
प्रस्ताव पर
- एकात्मक शासन प्रवृत्ति — आपातकाल, राष्ट्रपति शासन के समय
- समवर्ती सूची में संसद का पंचस्य
- एकल नागरिकता,
- सामान्य संविधान संशोधन में राज्य को हिस्सा नहीं।
- अम-3 राज्य सीमा, नाम, परिवर्तन करने की शक्ति

इस प्रकार भारतीय संविधान  
संघीय संविधान को नम्यता व अनम्यता के  
साथ संगठित करता है।



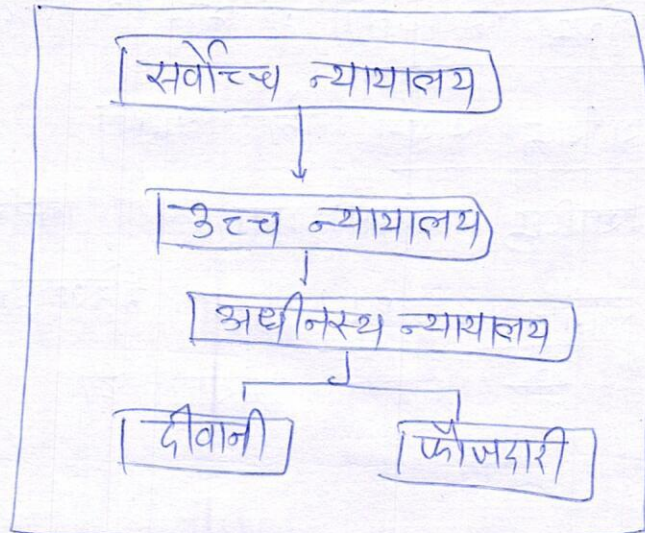
7. न्यायिक कार्यों की पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता एक सुदृढ़ एवं प्रभावी विधिक प्रणाली की आधारशिला है, जिससे लोक विश्वास सुनिश्चित और न्यायिक सिद्धांत का कार्यान्वयन संपुष्ट होता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The transparency and accountability of judicial function form the cornerstone of a robust and effective legal system, ensuring public trust and upholding the principles of justice. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)

Ans

भारतीय संविधान समेकित न्यायपालिका  
का गठन करता है जिसमें निम्न ढांचे को  
स्वीकार करता है।



# पारदर्शिता & जवाबदेहिता किस प्रकार आधारशिला हैं।

- न्यायिक विश्वास को बनाए रखती हैं
  - ↳ लोगों का जुड़ाव
- न्यायिक पारदर्शिता से न्यायिक मर्यादा में कमी
  - ↳ न्यायिक संप्रभुता को
  - ↳ न्यायिक सत्ता को सुनिश्चित करती हैं



→ न्यायिक जवाबदेहिता → न्यायिक दक्षता बढ़ानी है



न्यायिक परिणाम में  
तीव्रता

त्वरित  
वाद निपटारा ← केस  
निलंबन में  
कमी

→ न्यायिक नियुक्तियों में भर्षा-भर्षावाद को रोकने में  
सक्षम

न्यायिक संयम को बढ़ावा

न्यायिक अतिसक्रियता पर नियंत्रण

संज्ञान & PIL का उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वयन  
को बढ़ावा मिलना है।

इसलिए ऐशियन डेमोक्रेटिक

रिफ़ोर्म एसोसिएशन के शब्दों में कहे तो न्यायिक

पारदर्शिता व जवाबदेहिता लोकतांत्रिक जनवाणीदारी

व पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है।



8. राज्यों की राजनीतिक कार्यप्रणाली के संबंध में राज्यपालों के गैर-पक्षपातपूर्ण बने रहने से संबंधित संवैधानिक अवधारणा गहन जाँच के दायरे में है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The constitutional conception of state governors occupying a non-partisan position with regard to the political functioning of states has come under severe strain. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)

44

राज्यपाल की कार्यप्रणाली के  
कारण उस पर खबर का स्टाम्प तथा केन्द्र  
के एजेंट होने का आरोप लगाया जाता है।

आरोप  
के तर्क

- ① Art-200 का दुरुपयोग।
- ② अनु-20 के तहत अधिकार प्रसंगों  
को राष्ट्रपति के पास भेजना।
- ③ राज्य विधायिका के साथ टकराव।
- ④ अनु-356 & 365 का दुरुपयोग करना।
- ⑤ अनावश्यक रूप से फ्लोर टेस्ट करने  
के लिए प्रयास करवाना।
- ⑥ केन्द्र की ओर अधिक झुकाना तथा  
मंत्रिमण्डल के आदेशों की अवहेलना।
- ⑦ दिल्ली उपराज्यपाल विवाद।



उपर्युक्त कारणों से ~~इसके~~ संवैधानिक  
अवधारणा की जाँच की जानी चाहिए।

# जाँच के लिए राय / सुझाव :-

① सरकारी आयोग & पुरानी आयोग की सिफारिशों  
पर ध्यान दिया जाए।

- └ नियुक्ति में राज्य मुख्यमंत्री का योगदान
- └ नियमित कार्यकाल
- └ प्रसाद पर्यंत राष्ट्र की व्याख्या करें।

② संवैधानिक समीक्षा समिति (NCRWC) की सिफारिशों  
पर ध्यान दिया जाए।

③ बहुस्तरीय वार्ता - संवैधानिक थिंक टैंक + केन्द्र +  
राज्य सरकार + डिजिटल सर्वे  
+ Nho's के सहयोग से  
चर्चा की जाए।



9. "कारागार सुधार न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक विधिक एवं सामाजिक आवश्यकता भी है।" इस कथन के आलोक में भारत में कारागारों की स्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10
- "Prison reform is not just a moral imperative, but a legal and social necessity." In light of this statement, critically analyze the state of prisons in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)

Ans

भारतीय कारागार स्थल ओवर क्राउडिंग की समस्या से ग्रसित है। भारतीय जेलों की क्षमता 4 लाख है जबकि कैदियों की संख्या 4.88 लाख है। (NCRB ऑफ़िस)

# कारागारों की स्थिति :-

- ① ओवर क्राउडिंग की समस्या
- ② सामाजिक सुविधाओं का अभाव
  - └ CCTV कैमरे नहीं।
  - └ महिला कैदियों के लिए शौचालय & स्नानागार नहीं।
- ③ रहन-सहन का निम्न स्तर
  - └ सफाई का अभाव
  - └ दिसो के अनेक अवसर
  - निम्न स्वास्थ्य स्तर



- ④ कारागार में बढ़ती हिंसा
- ⑤ कारागार के प्रभावी विनियमन का अभाव
- ⑥ कारागार में मानवाधिकार उल्लंघन  
↳ मानवाधिकार आयोग २ प्रशासन  
द्वारा समय पर जांच नहीं।

# way forward:-

- ① Best model - सिंगापुर - Yellow ribbon model  
↳ कैदियों पर येलो रिबन लगाकर acknowledging  
की जाए।
- ② model कारागार कानून लाया जाए।
- ③ कारागार सुधार के लिए अवसरचन। खर्च।
- ④ पुनर्वास नीति का निर्माण।

इस प्रकार कारागार सुधार एक  
नैतिक, सामाजिक, व विधिक अनिवार्यता बन गई है।



10.

भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।

(150 शब्द) 10

Discuss the need for an All-India Judicial Service (AIJS) in India, highlighting key issues and challenges in its implementation.

(150 words) 10

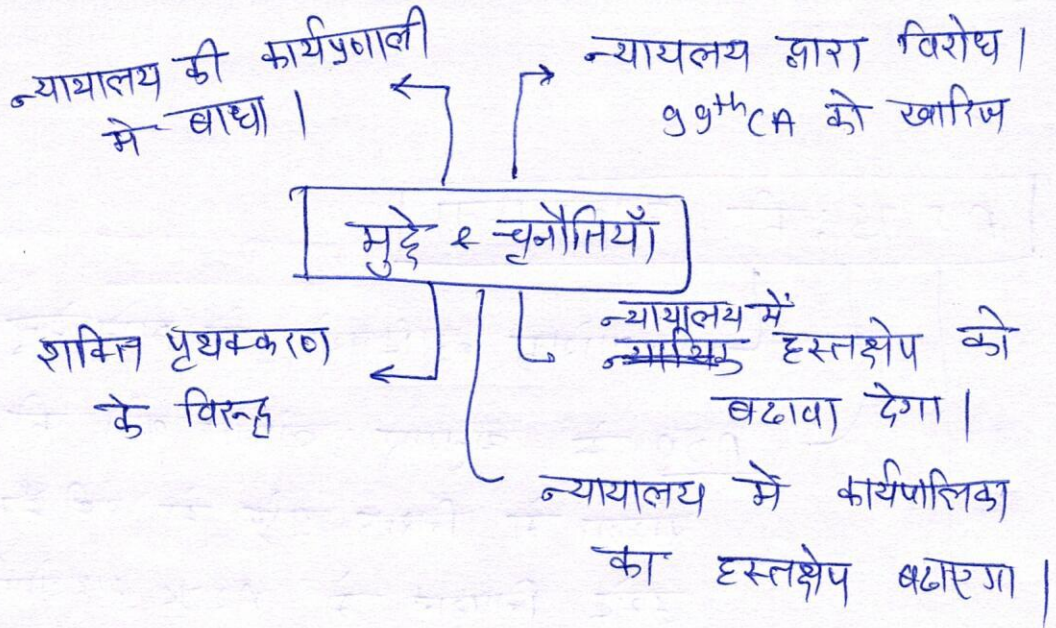
उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)

4

## AIJS की आवश्यकता

- न्यायिक न्युक्तियों को भरने हेतु।
- ADR के अनुसार लेखित वादों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।  
इसे निपटान में AIJS सहयोगी हो सकता है।
- न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता को लाने में सहयोगी।
- न्यायलयों के लोकतांत्रिकरण के लिए अभिवार्य।
  - महिलाओं के अवसर में वृद्धि करेगा।
  - दलित/SC/ST वर्ग की नियुक्तियों में वृद्धि की सम्भावना।
- अखिल भारतीय स्तर पर न्यायिक सेवाओं में एकता।
- रोजगार के अतिरिक्त अवसर।





# क्या किया जाए ?

- ① न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम व्यवस्था में ही सुधार किया जाए ।
- ② न्यायालय + सरकार + विपक्ष + सर्वेधानिष्ठ थिंक टैंक का वार्तामंच बनाकर निर्णय लिया जाए ।



11.

सराहनीय प्रयासों के बावजूद, भारत की जनजातीय जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाओं के सफल वितरण में विभिन्न चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Despite commendable efforts, there are several obstacles that hinder the successful delivery of healthcare services to the tribal population of India. Analyse.

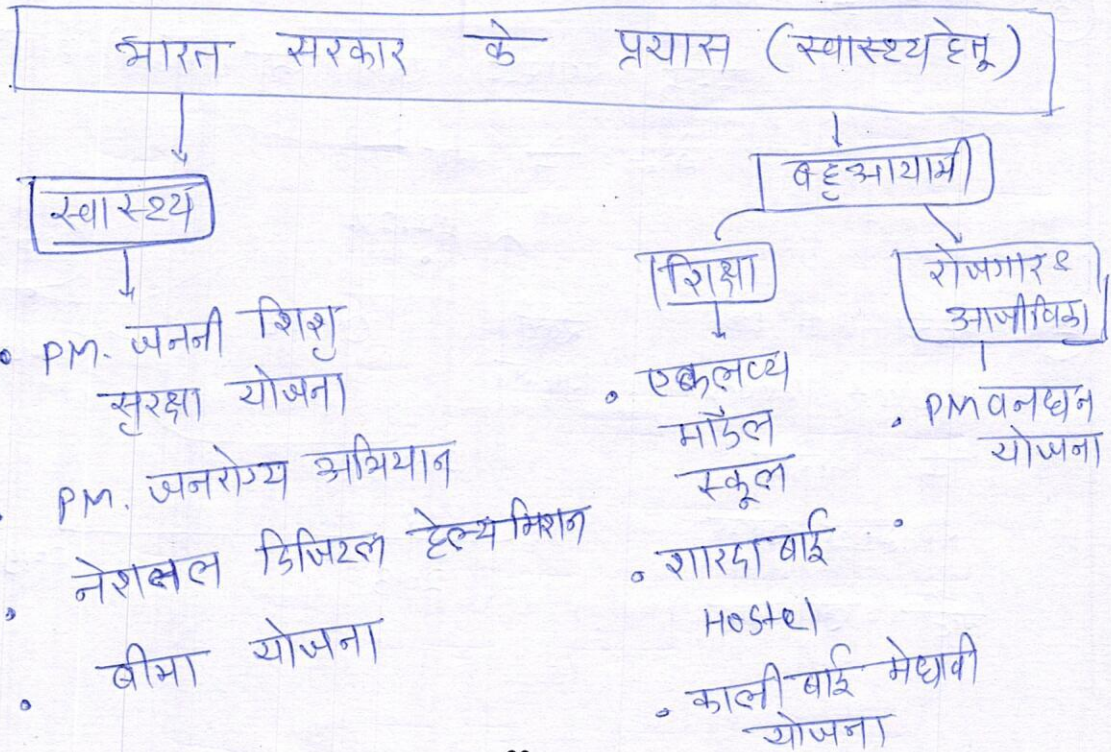
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)

जनजाति

लोकुर समिति - 1965 के अनुसार

वे समुदाय जो पिछड़ी-हुई, परम्परागत व आदिम कृषि प्रणालियों, सामाजिक पृथक्करण तथा सम्पर्क में द्विचक्रादृष्ट (भौतिक सम्पर्क नहीं) से ग्रसित हैं, उन्हें जनजातीय वर्ग में रखा जाना चाहिए।

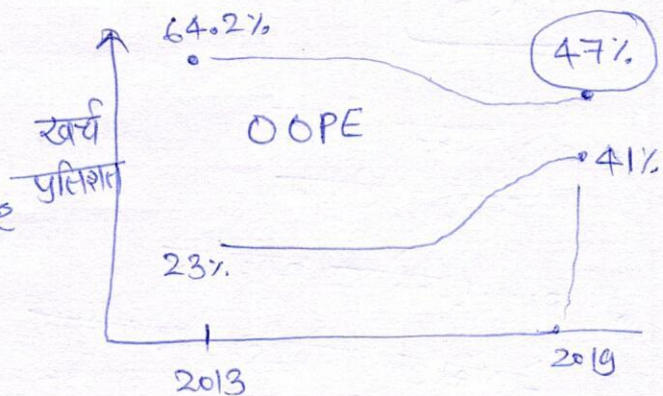




उपर्युक्त सुविधाओं के बावजूद  
वांछित परिणाम में निम्न चुनौतियाँ रही हैं—

- ① योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार & सीकेजिंग  
↳ Rajiv. गाँधी ( 1 रु का केवल 16 पैसे  
अनता तक जाता है।
- ② अनजातीय वर्ग में शिक्षा का निम्न स्तर  
↳ वर्ग असमान ( 20% से 44% तक शिक्षा  
स्तर)
- ③ गरीबी → अनजातीय वर्ग में गरीबी की प्रधानता  
उनके स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाती है तथा  
बोझ के रूप में।

- ④ उच्च out of pocket expenditure  
के कारण  
स्वास्थ्य लाभ  
नहीं ले पाए।





- ⑤ स्वास्थ्य अवसरचना पर कम खर्च ।
- ⑥ NHGs & SHGs की पहुँच नहीं हो पाई ।
- ⑦ जनजातीय वर्ग का अपराधीकरण  
Lex. (mp. में 2019) के कुल अपराध का 34% जनजाति
- ⑧ योजनाओं के बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है इसके कारण सक्षम लक्षित स्वास्थ्य नीति निर्माण नहीं हुआ ।

"क्या किया जाए" - ?

- ① एकलव्य अस्पतालों का निर्माण
- ② लक्षित नीति निर्माण किया जाए ।
- ③ स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य को NHGs & SHGs के द्वारा जनजातीय समुदायों तक पहुँचाया जाए ।
- ④ क्षेत्र आधारित विशेष योजनाओं का निर्माण करे ।
- ⑤ राज्य सरकारों को स्वास्थ्य पर अधिक बल देना चाहिए ।
- ⑦ बहुदलधारक मंच & निजी अस्पतालों को सुविधाजनक बनाया जाए ।



12.

विधायी अंग के रूप में संसदीय कार्यों की गणना कीजिये। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय संस्था और उसकी प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने हेतु सुधार एवं तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई अनिवार्य है? (250 शब्द) 15

Enumerate the functions of Parliament as the legislative organ. Do you agree that reforms and urgent remedial action seem imperative for making parliamentary institutions and processes effective?

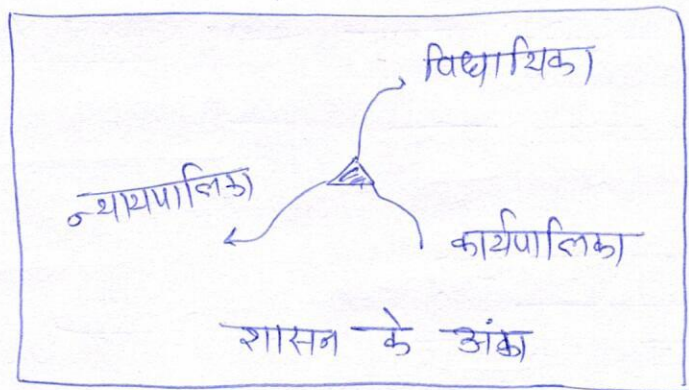
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

44

भारत संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाता है जिसमें नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख के साथ-साथ संसद की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।



# विधायिका के कार्य :-

- ① कानून निर्माण का कार्य
- ② विभिन्न प्रस्तावों को लाना
- ③ राष्ट्रपति अध्यादेशों को अनुमति प्रदान करना
- ④ राष्ट्रीय आपातकाल & राष्ट्रपति शासन को सहमति/असहमति प्रस्ताव पारित करना



**वित्तीय कार्य** → विनियोग विधेयक पर चर्चा & पारित करना  
बजट पारित करना  
अनुदान की मांगों पर मतदान करना।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)

**न्यायिक कार्य** → राष्ट्रपति महाभियोग पर मतदान करना  
राज्यपाल (राज्य विधायिका द्वारा) के  
न्यायधिश के द्वारा संबंधी प्रस्ताव  
पर मतदान करना।

**कार्यपालिका** → कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना  
प्रश्न काल में प्रश्न प्रश्नना  
द्वयानाकर्षण प्रस्ताव, निर्दोष प्रस्ताव  
मंत्रिमण्डल की राय जानना, प्रश्न प्रश्नना

लेकिन संसद में कुछ समस्याएँ हैं ?

कार्य समय	बिल को	सदस्यों	सदन में	महिला
में कभी	समितियों	की	अपराधिक	सदस्यों
↓	तक कम	अधिक	प्रवृत्ति	की
राज्यसभा व	पहुँचाना	अनुपस्थिति	के नेताओं	संख्या
लोकसभा	↓	↓	में वृद्धि	कम
के लिए	केवल 11% महिला		↓	↓
अलग-2	मेरे 17 <sup>th</sup> लोकसभा		(17 <sup>th</sup> लोकसभा में 29% पर 74 सदस्य)	



## # कार्यवाही के तत्व # सुधार के सुझाव #

- ① बायोमेट्रिक उपस्थिति तंत्र अनिवार्यता
- ② संसद के कार्य समय की ऑडिटिंग हो।
- ③ अत्यधिक अनुपस्थिति के निर्देश का आचार बनाया जाए।
- ④ विपक्ष का सशक्तीकरण व शेडो कैबिनेट के निर्माण पर ध्यान।
- ⑤ यूथ पार्लियामेंट संस्कृति को बढ़ावा देवे।
- ⑥ अपराधीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ECI व SC के रामबाबु ठाकुर वाद के दिशा-निर्देशों का सहारा लिया जाए।

इस प्रकार उपर्युक्त सुझावों सहित अन्य उपायों को अपनाते हुए विधायिका कार्य प्रणाली दक्षता को बढ़ावा देकर शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहिए जो कि संसदीय दक्षता व प्रभावशीलता में वृद्धि करेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)



13.

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कम विरोधाभासी होने के साथ विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। चर्चा कीजिये। इस दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं?

(250 शब्द) 15

Alternate Dispute Resolution mechanisms are less adversarial and can provide a better substitute to the conventional methods of resolving disputes. Discuss. What are the government's efforts to bring out a transformative shift towards it?

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।

(Candidate must  
not write on this  
margin)





उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)



उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)



14.

दिल्ली के शासन और भारत के संघीय ढाँचे पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (GNCTD) (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Critically examine the provisions of the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) (Amendment) Act, 2023 considering its potential impact on the governance of Delhi and the federal structure of India.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान भारत को संघीय स्वरूप प्रदान करता है। जिसमें केन्द्र व राज्य दोनों स्तर पर अलग-अलग सरकारें होती हैं।

# दिल्ली शासन & संघीय व्यवस्था

अनुच्छेद-2 में दिल्ली केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में वर्णित है।

लेकिन

अनु- 239(A) दिल्ली के लिए पृथक् विधानसभा का प्रावधान करता है। इस प्रकार दिल्ली में विधानमण्डल है जिसका एक मुख्यमंत्री होता है तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल का प्रावधान किया गया है।



स संबंध विषय - भूमि, पुलिस व दैनिक कार्य

के राज्य सूची - उपर्युक्त के अलावा सभी विषय  
राज्य के पास होंगे

(69<sup>th</sup> संविधान संशोधन से ये प्रावधान किए गए)

न UNCTD अधि. 2023 प्रावधान :-

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)





उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)



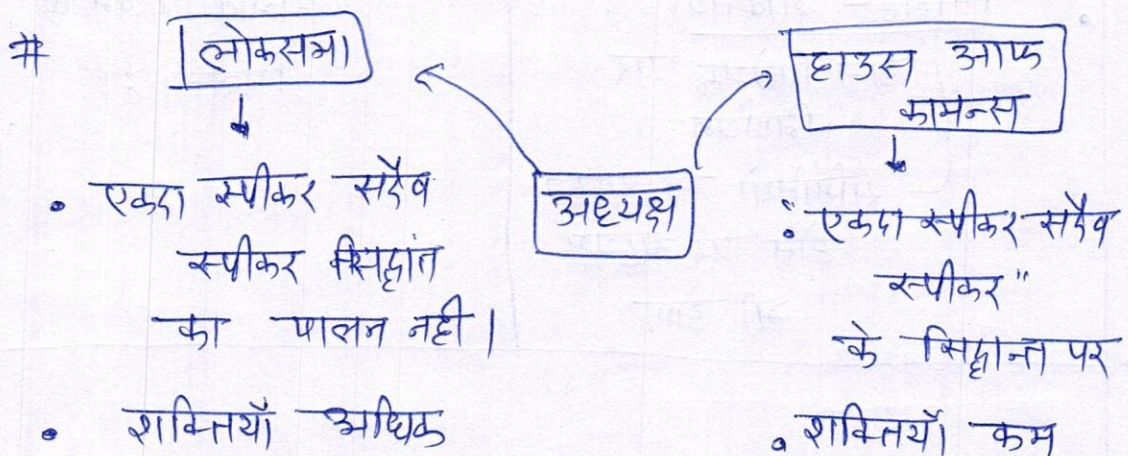
15. भारतीय लोकसभा और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अध्यक्ष की भूमिका की तुलना कीजिये। चर्चा कीजिये कि ये भूमिकाएँ अपने-अपने विधायी निकायों की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करती हैं। (250 शब्द) 15

Compare and contrast the role of speaker in the Indian Lok Sabha and British House of Commons . Discuss how these roles impact the functioning of their respective legislative bodies. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)

### भारत तथा ब्रिटेन दोनों

संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने हुए ब्रिसदन  
(ऊपरी सदन & निम्न सदन) प्रणाली को स्वीकार  
करते हैं। ब्रिटेन के निम्न सदन को हाउस  
ऑफ कॉमन्स तथा उच्च सदन को हाउस  
ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है व भारत के ऊपरी  
सदन को राज्यसभा तथा निम्न सदन को  
लोकसभा कहा जाता है।





• अद्यक्ष बनने के बाद पद से इस्तीफा नहीं देता है।

• राजनीतिक पहचान व राजनीतिक पार्टी को बनाए रखता है।

• दल-बदल पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार

• एक विशेष लिखित नियमावली से पद का क्रियान्वयन

• विशिष्ट शक्तियाँ  
 { धन विधेयक पर निर्णय  
 समितियों का सदस्य होने पर अध्यक्ष भी होगा

• अद्यक्ष बनने के बाद पद से इस्तीफा देता है।

• राजनीतिक पार्टी को छोड़ देता है।

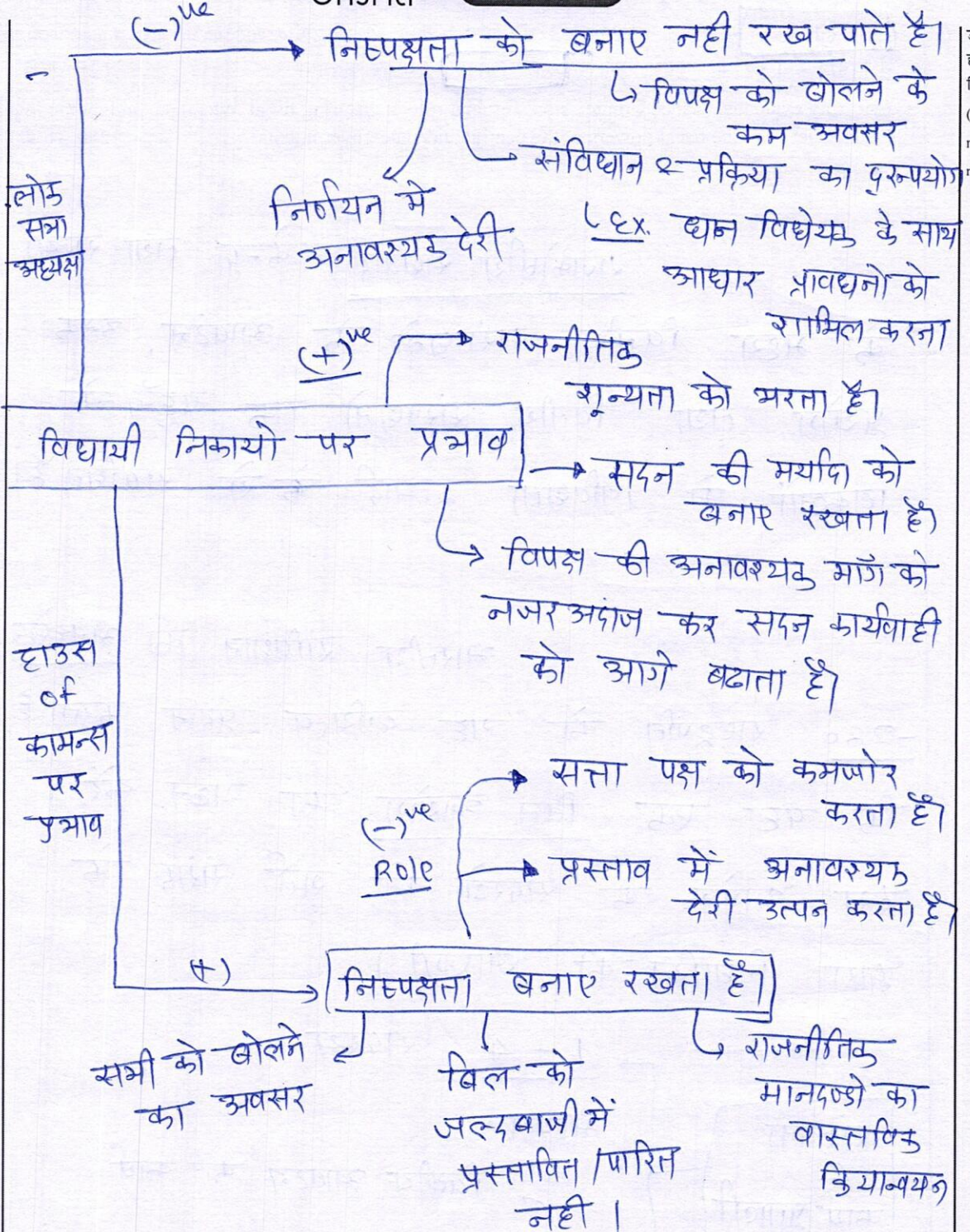
• दल-बदल निर्णय शक्तियों का अभाव

• परम्पराओं (संसदीय) पर सदन का क्रियान्वयन

• विशिष्ट-शक्तियों का अभाव देखने को मिलता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)





उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)



16. राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने एवं केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

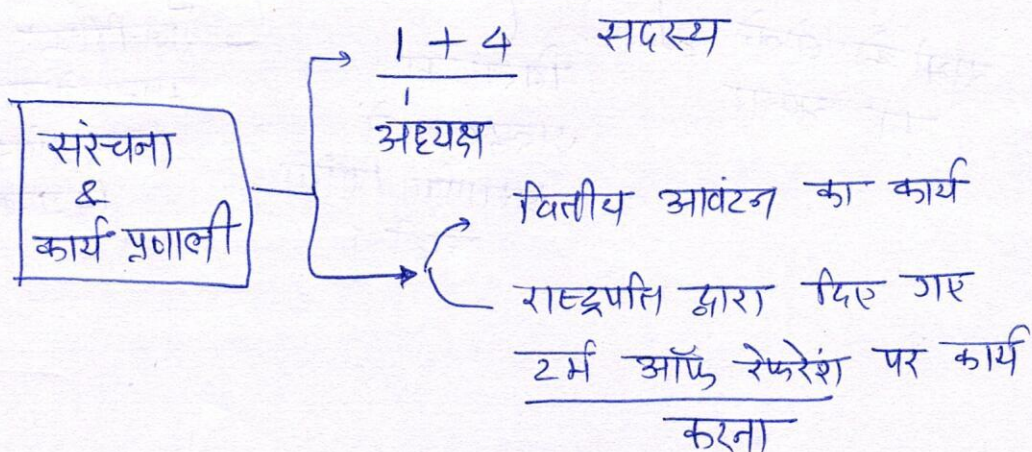
Critically evaluate Finance Commission's crucial role in ensuring fiscal federalism and maintaining a balance between the fiscal powers of the central and state governments. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

राजकोषीय संघवाद केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के आवंटन, उनके प्रयोग तथा वित्तीय संसाधनों तक पहुँच के विकल्पों में विविधता इत्यादी के से संबंधित है।

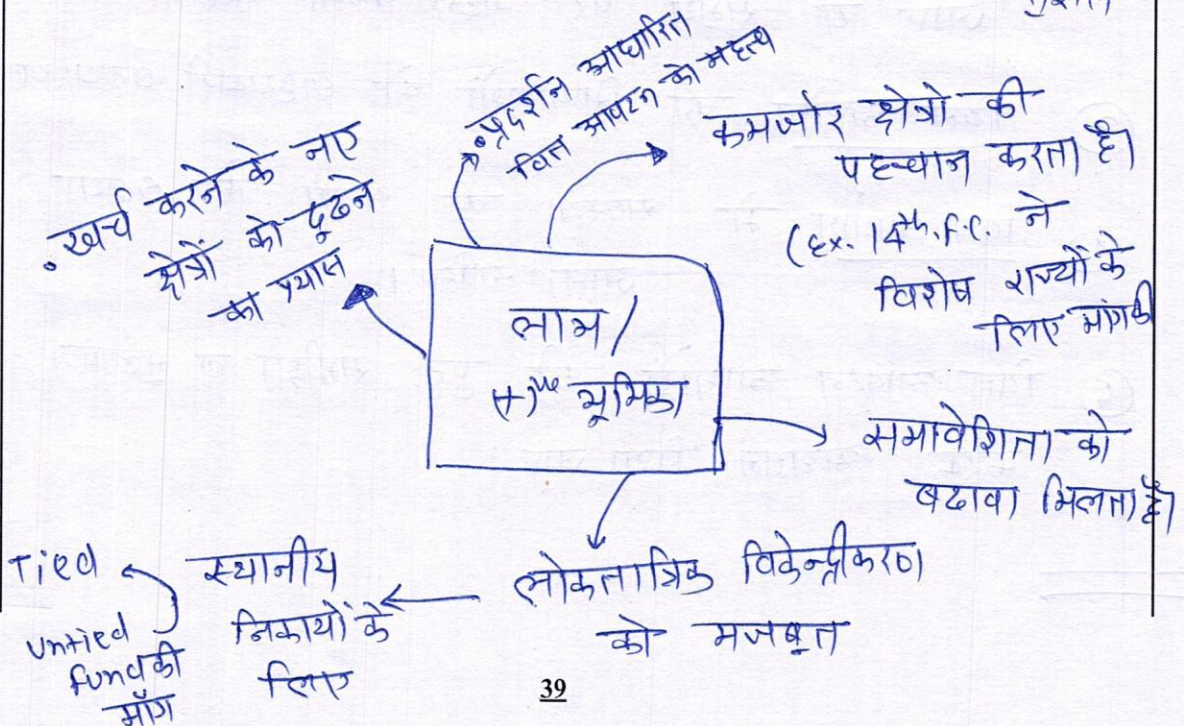
भारतीय संविधान का अनुच्छेद -280 राष्ट्रपति को यह दायित्व प्रदान करता है कि वह एक वित्त आयोग का गठन करें। इस आयोग के सदस्यों की शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित की जाएगी।



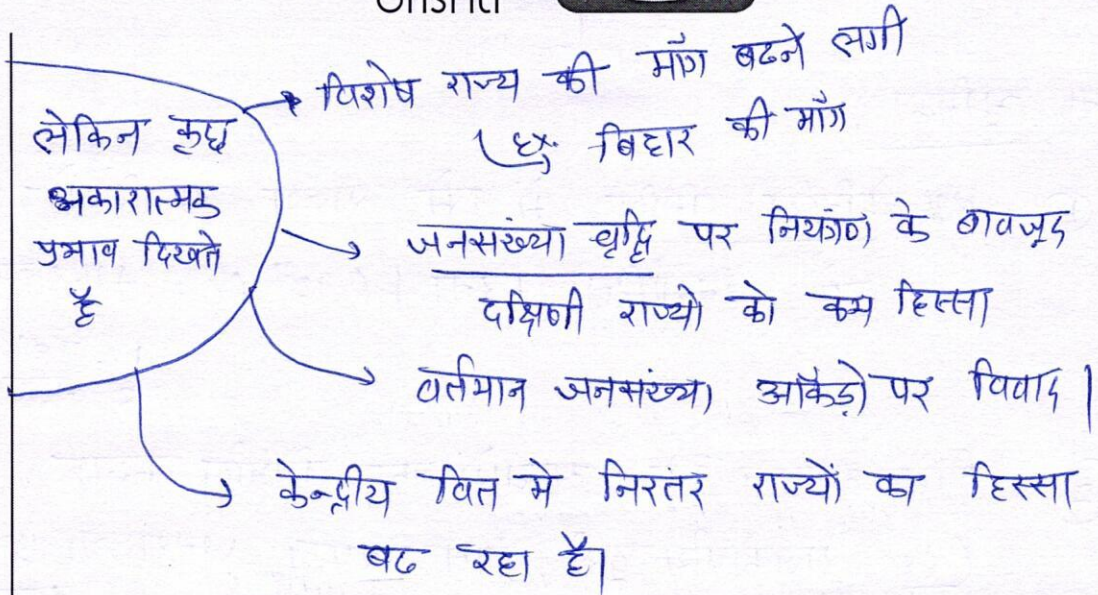


# भूमिका :-

- ① केन्द्रीय निधि में से राज्य के हिस्से को निर्धारित करना। (15<sup>th</sup> F.C = 41% राज्य + 1% J&K & लद्दाख)
- ② पित आवंटन के आधारों का निर्माण करना  
(Ex. राजकोषीय दूरी, जन क्षेत्रफल, जनसंख्या) - 1971 इत्यादि
- ③ स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की सिफारिश करना
- ④ राज्य विशेष, क्षेत्र विशेष के लिए मांगे करना।
- ⑤ आपदा, समाज कल्याण के लिए सिफारिश करना  
(Ex.) 15<sup>th</sup> F.C आपदा राहत निधि बनाने का सुझाव







### # way forward #

- ① राष्ट्रपति द्वारा दिए गए टर्म ऑफ रेफरेंस में सुधार किया जाए।
- ② राज्य वित्त आयोग के गठन को भी महत्व दिया जाए व समय पर गठन किया जाए।
- ③ वित्त आयोग की सिफारिशों को बाध्यकारी बनाया जाए।
- ④ वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए।
- ⑤ वित्त आवंटन आधारों की पुनः समीक्षा व मूल्यांकन करके अद्यतन किया जाए।



17.

क्या भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिये अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाया है? विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Has India leveraged its soft power to enhance its global stature and influence? Analyze.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)

Ans

सॉफ्ट पावर विदेश नीति में  
सांस्कृतिक तत्वों को समावेशित करने तथा  
उन्के आधारों पर अपने सामरिक व कूटनीतिक  
हितों की पूर्ति करने का विकल्प है।

हैं, सॉफ्ट पावर का लाभ उठाया है।

(A) पड़ोसी राज्यों के साथ

① नेपाल के साथ भारत अपने soft power का  
प्रयोग करके संबंधों के निमिति पर बल देता है।

Ex. ① नेपाल बुद्ध की जन्मभूमि, भारत बुद्ध की  
कर्म भूमि।

② नेपाली लोगों के लिए त्वांगमठ को  
खोला व पूजन का अवसर वही नेपाल  
के मंदिरों में भारतीय पूजारी।

# इस प्रकार अनधारणा का निमिति किया #



क) श्रीलंका के साथ सस्कृति का प्रयोग करते हुए  
रामायण सर्किट का निर्माण तथा भारत में श्रीलंकाई  
लोगों के लिए बौद्ध सर्किट का निर्माण।

ग) दक्षिण-पूर्वी एशियाई लोगों के साथ -

सिस्टर सिटीज के द्वारा  
इन्डोनेशिया के (छ-वियतनाम की दो चिन्ह मिन्ह  
साथ संबंध निर्माण व भारत की मदुरै।  
मे पाल वरस का  
प्रयोग २ अणकोरवा २  
मंदिर

घ) अफ्रीकी देशों के साथ :-

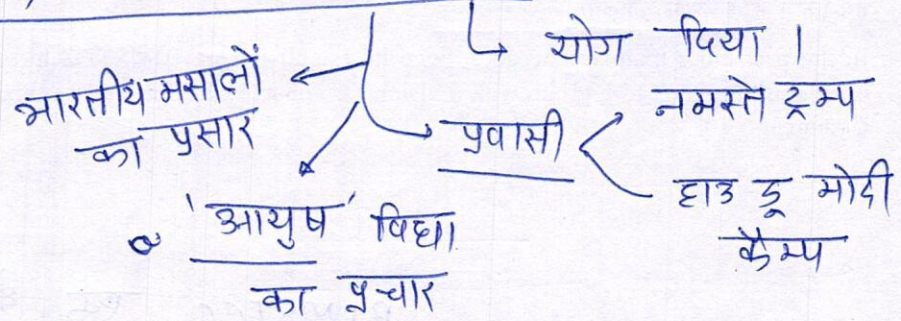
सांस्कृतिक  
प्रचार से।  
(शिक्षण के लिए और  
छात्रों में)  
मॉरीशस जैसे देशों में प्रवासी  
भारतियों के संबंधों से।  
भोजपुरी ६ अन्य जातों का प्रचार

द) कैरेबियाई ६ लैटिन अमेरिकी देशों :- त्रिनिदाद लेबोनो

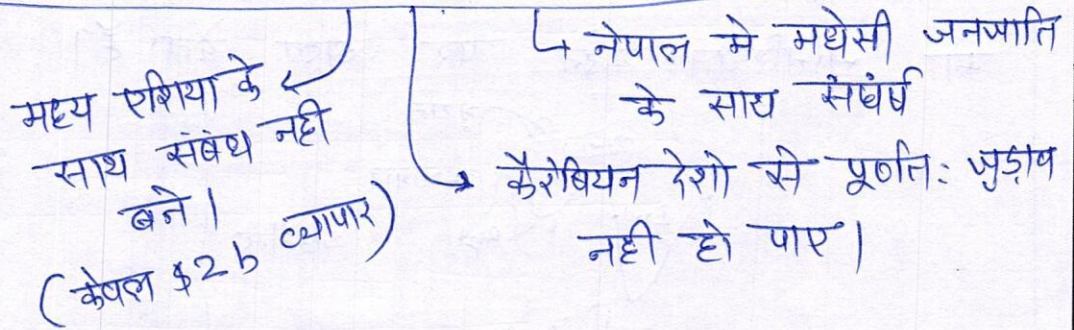
का तथा अन्य जगहों पर रेड इंडियस, भारतीय  
गिरमीरिया मजदूरों के साथ संबंध निर्माण से  
सरकारों के साथ संयोग soft power के  
उदाहरण हैं।



# यूरोप, & उत्तरी अमेरिका के साथ:-



लेकिन कुछ जगह प्रयोग नहीं हो पाया



इस प्रकार भारत को अपने सांस्कृतिक तत्वों के प्रचार के साथ-साथ इन देशों के साथ 'ड-स' (सम्मान, शांति, सुरक्षा, सहयोग से समृद्धि) तथा संबंधों को पुनः ऊर्जित बनाने के लिए 3 R (रेस्पेक्ट, रिकगनाइज, रिक्न्स्ट्रक्चर) सिद्धान्तों का पालन करते हुए साफ्ट पावर का प्रयोग करना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)



18.

अपनी स्थापना के बाद से पिछले दो दशकों से अधिक समय में, बिस्मटेक (BIMSTEC) ने अपनी विशाल क्षमता का उपयोग करते हुए सामूहिक उन्नति की दृष्टि वाले समूह के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में एक लंबा सफर तय किया है। टिप्पणी कीजिये।

(250 शब्द) 15

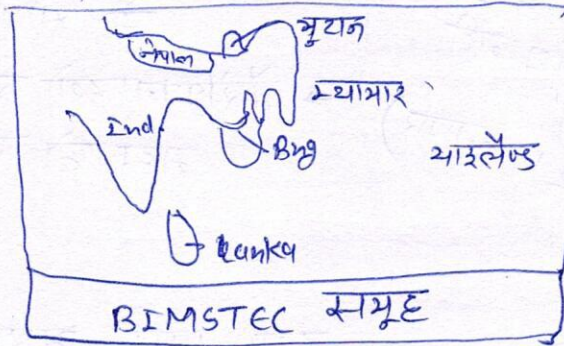
In the past more than two decades since its establishment, BIMSTEC has come a long way in distinguishing itself as a group with a vision for collective advancement utilizing its vast potential. Comment.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

BIMSTEC एक क्षेत्रीय समूह  
है जो अपनी क्षेत्रीय आर्थिक & तकनीकी समृद्धि को सुनिश्चित करने पर ध्यान देता है।



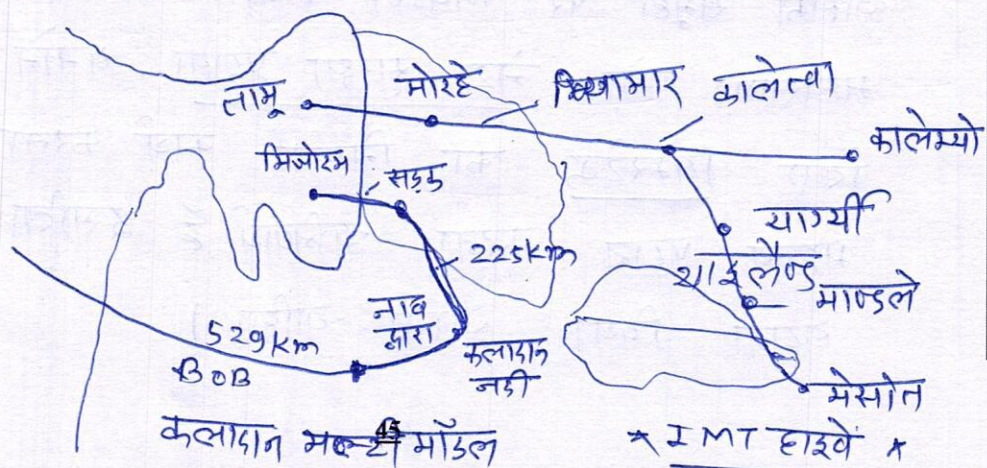
# BIMSTEC ने कैसे अलग पहचान बनाई -

- ① समूह ने कार्य क्षेत्र के लिए 16 क्षेत्रों की पहचान की। इन कार्यक्षेत्रों को प्रत्येक राष्ट्र के लिए विभाजित कर दिया। कार्य विभाजन के इसी स्वरूप ने BIMSTEC को अन्य से अलग बना दिया।



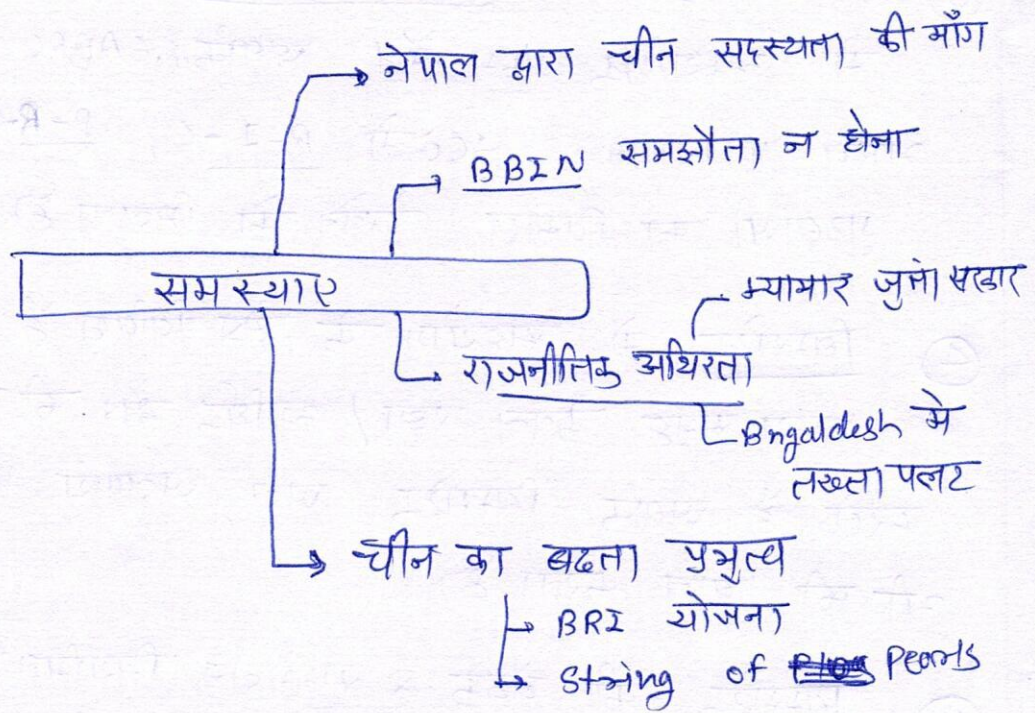
उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)

- ② सभी देशों में क्षेत्रीय जुड़ाव है जबकि SAARC में यह जुड़ाव नहीं था।
- ③ इस समूह में द्विपक्षीय विवाद अन्य की तुलना में अत्यधिक कम हैं। जबकि SAARC में भारत - पाकिस्तान, SCO में R-I-C, P-R-C त्रिकोण गुटबाजी का विकास देखने को मिलता है।
- ④ विम्सरेड में सहयोग के क्षेत्र विविध हैं जबकि अन्य समूह केवल रक्षा / आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं जबकि विम्सरेड जल, जलवायु, परिवहन भी की बात करता है।
- ⑤ विम्सरेड की बैठके २ सम्मेलन नियमित रूप से होते हैं।
- ⑥ विम्सरेड के कार्य :-





विम्सट्रेड क्षेत्र में विस्तृत अवसरचर्चा निर्माण के कारण कम समय में अधिक सहयोग किया है। लेकिन कुछ समस्याएँ अभी भी हैं।



अतः उग्रवाद नियंत्रण में भूमिका, N-E से जुड़ाव, असंगठित अपराध को रोकथाम में सहायक, आतंकी समूहों पर नियंत्रण तथा भारत को हिन्द महासागर में नेट सुरक्षा प्रदाता बनाने के लिए विम्सट्रेड का निरन्तर कार्य करना तथा महत्व प्रदान करना अनिवार्य है इसलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)



19.

उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते वैश्विक ऋण संकट के अंतराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रमुख परिणामों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Examine the major outcomes of soaring global debt crisis in emerging and developing economies on international relations. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)

Ans

विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ





उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।

(Candidate must  
not write on this  
margin)



उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)



20.

यूरोप का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर बढ़ता ध्यान तथा भारत के साथ गहराता आर्थिक और तकनीकी सहयोग परस्पर लाभ प्रदान करता है। चर्चा कीजिये।

(250 शब्द) 15

Europe's increased focus on the Indo-Pacific and the deepening economic and technological collaboration with India offer mutual benefits. Discuss.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।

(Candidate must  
not write on this  
margin)

" हमारे लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र का अर्थ उस क्षेत्र से है जो अफ्रीका के पूर्वी तट से अ उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट तक विस्तृत है। "

• ड. जयशंकर •

यूरोप का हिंद प्रशांत क्षेत्र में

निरन्तर ध्यान बढ़ रहा है।

Ex.

- AUKUS ( UK का योगदान बढा )
- ब्लू डोट नेटवर्क
- इंडियन कोशियन रिम असोसिएशन में  
फ्रांस की बढ़ती भूमिका
- यूरोपीय उपनिवेशों पर निरन्तर  
सघर्षों में वृद्धि
- हिन्द महासागर क्षेत्र में तेल & गैस  
कुओ का निष्कर्षण & बहुधातिय खनिजों  
का खनन ।



## # भारत के साथ गहराता आर्थिक & तकनीक सहायता

यूरोपियन  
यूनियन से  
FTA

EU के साथ  
तकनीकी  
समझौता

फ्रांस से  
रक्षा आयात  
→ राष्ट्रीय  
विभाग

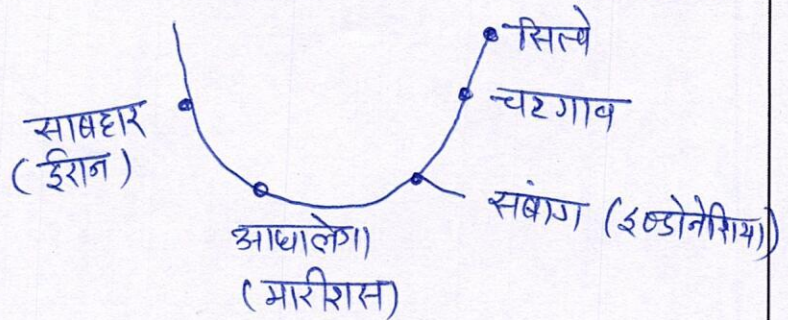
इटली के  
समर्थ  
रक्षा  
समझौता - 2023  
प्रवास &  
आपूर्ति  
समझौता - 2024

## ii किस प्रकार लाभ देगा

→ खुले & मुक्त द्विदिश प्रशात क्षेत्र का निर्माण करेगा।

→ चीन के प्रभुत्व को कम करेगा।

→ भारत के Necklace of diamond को समर्थन

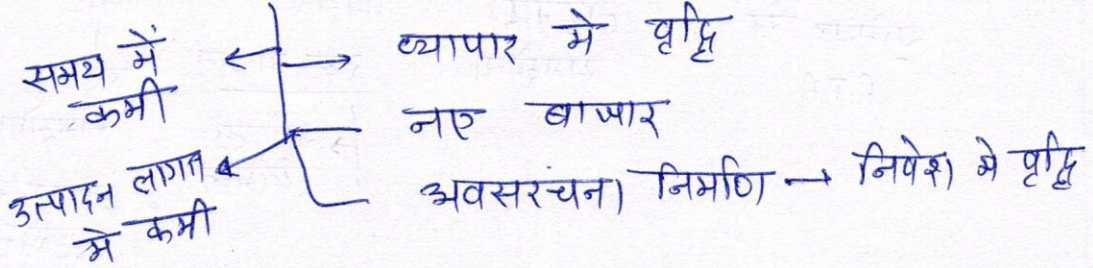


Coastal Surveillance Radar की  
स्थापना में सहयोग व यूरोप के  
उपनिवेशों पर लागू करों का समर्थन



1. हिन्द महासागर में भारत के वरिष्ठ को सीक्वर करता है

2. IMCC का समझौता



इस प्रकार सहयोगी यूरोप

हिन्द प्रशांत क्षेत्र में एक जुड़ी हुई - मजबूत  
- पारदर्शी - व निष्पक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था का  
निर्माण करेगा ।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं  
लिखना चाहिये।  
(Candidate must  
not write on this  
margin)





Space for Rough Work  
(रफ़ कार्य के लिये स्थान)

निष्पक्ष  
मजबूत  
पारदर्शी  
युष्म





Space for Rough Work  
( रफ कार्य के लिये स्थान )





Space for Rough Work  
(रफ़ कार्य के लिये स्थान)





Space for Rough Work  
(रफ़ कार्य के लिये स्थान)